

परियोजना का नाम-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मजगाँव
तहसील का नाम काठसर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडी देवी के रंगेश मोट्टा मार्ग के चौनाला मोट्टा मार्ग के निर्माण हेतु (00 हे० आरक्षित वनभूमि 1.050 हे० सिविल सोयम भूमि 00 हे० वन पंचायत भूमि 00 हे०) अर्थात् कुल 1.050 हे० वनभूमि का 100 नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मजगाँव द्वारा दिनांक 06/11/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मजगाँव के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि 100 नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत मजगाँव
वि० ४००००० (बागेश्वर)


ग्राम पंचायत मजगाँव
वि० ४००००० (बागेश्वर)

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम- कमेडी देवी-सुराकोट मोक्षार्थ के लिए श्री 02-से संयुक्त-मजगांव-धौलाहा.
मोहर-मार्ग का निर्माण.

दिनांक 06-11-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत, मजगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री. सी. एस. रावत पु. श्री. पं. सठक	श्री. रावत 06/11/2015
2-	जगदीश सिंह पु. श्री. विश्वसिंह	जगदीश
3-	देवेंद्र सिंह पु. श्री. दापान सिंह	देवेंद्र
4-	दुर्गेश सिंह पु. प्रताप सिंह रावत	दुर्गेश
5-	दीप सिंह पु. लक्ष्मण सिंह	दीप सिंह
6-	अमला देवी पु. सुन्दर सिंह	अमला देवी
7-	श्री. रावत पु. हरीश सिंह रावत	श्री. रावत
8-	श्री. रावत पु. रावत	श्री. रावत
9-	दीप सिंह पु. श्री. रावत	दीप सिंह
10-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
11-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
12-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
13-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
14-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
15-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
16-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत
17-	श्री. रावत पु. श्री. रावत	श्री. रावत

वन पंचायत मजगाँव की बैठक कार्यवाही

दिनांक 06/11/15 को वन पंचायत मजगाँव की बैठक हुई जिसमें ~~महोदय~~ ^{कपकोट} ~~मजगाँव~~ ^{मजगाँव} से रंगधरा मजगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया कि-

- मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक - 06/11/2015

स्थान - मजगाँव

ह0

सरपंच

सरपंच

वन पंचायत मजगाँव

पौ0 - मन्दील, जिला-नागपुर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत -

1. हरिश्चन्द्र सिंह रावत सरपंच
2. जगत सिंह रावत सदस्य
3. भूपेन्द्र सिंह सदस्य
4. नारायण सिंह सदस्य
5. पार्वती देवी सदस्य
6. देवा देवी सदस्य
7. खुशहाल सिंह सदस्य
8. आनन्द सिंह सदस्य
9. नन्दा देवी सदस्य

सरपंच

सरपंच

वन पंचायत मजगाँव

पौ0 - मन्दील, जिला-नागपुर

वन पंचायत मणगाँव की बैठक कार्यवाही

दिनांक 06/11/15 को वन पंचायत मणगाँव की बैठक हुई जिसमें 27/10/15 को दिनांक 2 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया कि -

- मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक - 06/11/2015

स्थान - मणगाँव

ह0

सरपंच

सरपंच

वन पंचायत मणगाँव

पिन - 161001, जिला - जयपुर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत -

- 1- हरिश्चंद्र सिंह रावत सरपंच
- 2- जति सिंह रावत सदस्य
- 3- भूपेन्द्र सिंह सदस्य
- 4- नारायण सिंह सदस्य
- 5- पारस देवी सदस्य
- 6- देवी देवी सदस्य
- 7- सुरेश चेल सिंह सदस्य
- 8- आनन्द सिंह सदस्य
- 9- लाल देवी सदस्य

सरपंच

सरपंच

वन पंचायत मणगाँव

पिन - 161001, जिला - जयपुर

ग्राम पंचायत का नाम—बै. नाला
तहसील का नाम—काठडा जिला—बगेश्वर

उत्तराखण्ड में जनपद काठगढ़ के अन्तर्गत रा.रा.अ.गै.व. परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वनभूमि 1.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 1.00 हे० वनभूमि का ले.सि.वि.रु.प.क. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोसला द्वारा दिनांक 2-11-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजित एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जे.प.वा. के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि जे.प.वा. नि.क.प.क.दे. प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

[Handwritten signatures and stamps are present over the typed text.]

उद्देश्य 2-11-2015
कमान
राम बहादुर चौधरी
सौ. रमेशचंद्र, तह. कानडा
विपक्ष कमान प्रमाण-बागीरथ

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जावेगा।

वन पंचायत - चौनाला की बैठक कार्यवाही

दिनांक 30.10.2015 की वन पंचायत - चौनाला की बैठक हुई जिसमें

निर्माण कार्यवाही हेतु उपस्थित पारित किया गया कि - चौनाला मोटर मार्ग

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :- 30/10/2015

स्थान :- चौनाला

H0
Sarpanch
सरपंच
वन पंचायत चौनाला
कपकोट जिला - कानूरवट

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

कुमारी देवी

नन्दी देवी

पारवती देवी

दयानन्द

Sarpanch
सरपंच
वन पंचायत चौनाला
कपकोट जिला - कानूरवट

144-23.2

परियोजना का नाम :- बसोही ट्रेन्स-हार्वाक मुंबासाई वी फिगो 2 जैसे रंथार फमगौक
गोबोला गोदर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड स्तरीय समिति, कांसा

उपखण्ड कांसा परिक्षेत्र के अन्तर्गत एजेन्सी में १०० हे० आरक्षित वन भूमि है। २५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ७५ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १६५ हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरोधित जिनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कांसा) की दिनांक २३/११/२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मौमनियर कोटवा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:

श्री प्रदीप रेखा कोटली उपजिलाधिकारी

श्री सत्यनारायण प्रसाद

श्री समस्त नारायण सहायक सभाज कल्याण अधिकारी

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

कि रूमेड़ी देवी - राणा के मोहर मार्ग के निर्माण 2 रू संघरामजी के परियोजना है 1.50 हे० वन

प्रयोजित एजन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। लकड़ों की भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर श्रावणिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उम्र प्रभागीय वनाधिकारी, कॉलेज 2002 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से भारतीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संघ में ग्राम समूह/गंघरायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपर्युक्त सदस्यीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

दस्तावेज में सर्वसम्मति से समस्त काग्रेस कार्यकर्ता के अन्तर्गत
सिद्ध काग्रेस कार्यकर्ता के निर्माण हेतु 1050
 हे० एन० भूमि काग्रेस कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से सहमत प्रमाणित कर
 प्रत्यापित किए जाने पर सहमति प्राप्त की गयी।

काग्रेस
समस्त
कार्यकर्ता
काग्रेस
कार्यकर्ता

उप जिलाधिकारी / काग्रेस
 समस्त स्तरीय वन अधिकार समिति
 सहस्रील काग्रेस
 जगपद काग्रेस

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी काग्रेस को सूचना एवं आवश्यक जानकारी हेतु।

काग्रेस
समस्त
कार्यकर्ता
काग्रेस
कार्यकर्ता

उप जिलाधिकारी / काग्रेस
 समस्त स्तरीय वन अधिकार समिति
 सहस्रील काग्रेस
 जगपद काग्रेस

परियोजना का नाम कोरी देवी-स्योकोट मोट मार्ग के निर्माण से रंगहरा-मजगांव-चौकाला मोट मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, काठग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, काठग

उपखण्ड काठग प्रखण्ड के अन्तर्गत रंगहरा-मजगांव-चौकाला
मोटे मार्ग में 80 हे० आरक्षित वन भूमि 1-050 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 12 हे०
वा पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1-050 हे० वन - भूमि) का
लगे निचि कपडा प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील काठग) की दिनांक 23/11/2015 की
सम्म बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
में कोरी देवी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्रीमती देवी देवी	उपजिलाधिकारी	
श्रीमान जय प्रकाश	प्रभागीय वनाधिकारी	
श्रीमान जय प्रकाश	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
श्रीमान जय प्रकाश	डी०डी०डी०	
श्रीमान जय प्रकाश	डी०डी०डी०	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि कोरी देवी स्योकोट मोट मार्ग के निर्माण से रंगहरा-

मजगांव-चौकाला मोट मार्ग परियोजना हेतु 1-050 हे० वन
भूमि लो० नि० वि० कपडा

लगे निचि कपडा प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला सम्भल नहीं है। तब
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सहसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रस्तावतन की अनुमति दी गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी कोरी देवी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं शाश्वती नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदन का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में आम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

दिनांक २०/०५/२०२० से आरम्भ में जारी किया गया है।
 संख्या: १०५०/२०२०
 २०/०५/२०२० को जारी किया गया है।
 प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रति प्राप्त कर
 प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रति प्राप्त कर

[Signature]
 [Stamp]
 [Text]

आप जिलाधिकारी / अमान
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील [Signature]
 जगपद [Signature]

प्रतिरिति जिलाधिकारी, [Signature]

को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

[Signature]
 [Stamp]
 [Text]

आप जिलाधिकारी / अमान
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील [Signature]
 जगपद [Signature]

परियोजना का नाम : रूखेरी देवी-सुगाकोट में 1000/100 हे. की सिमेंट रोड का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, काठमांडू

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, काठमांडू

उपखण्ड काठमांडू परिक्षेत्र के अन्तर्गत रूखेरी देवी-सुगाकोट में 1000/100 हे. की सिमेंट रोड का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 1000/100 हे. सिमेंट रोड सौभाग्य वन भूमि 1000/100 हे. वन भूमि 1000/100 हे. अर्थात् कुल 1000/100 हे. वन भूमि 1000/100 हे. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील काठमांडू) की दिनांक 23/11/2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।

श्री रूखेरी देवी उप जिलाधिकारी काठमांडू
श्री रूखेरी देवी उप प्रभागीय वन अधिकारी काठमांडू
श्री रूखेरी देवी सहायक सभाध्यक्ष कल्याण अधिकारी काठमांडू
श्री रूखेरी देवी सहायक सभाध्यक्ष कल्याण अधिकारी काठमांडू

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

रूखेरी देवी-सुगाकोट में 1000/100 हे. की सिमेंट रोड का निर्माण हेतु परियोजना हेतु 1000/100 हे. वन भूमि 1000/100 हे.

रूखेरी देवी-सुगाकोट में 1000/100 हे. की सिमेंट रोड का निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। उपर्युक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा स्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर शार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की अनुमति दी गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वन अधिकारी काठमांडू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों का पता/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा वनाधिकार जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमति जारी की जा सकती है।

वेकड में सर्वसम्मति से उपखण्ड ४२५/८३१ को अन्तर्गत
 १०६१/८३१/८३१/८३१ को निर्माण हेतु १०६१/८३१
 को अनुरोधित किया जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

महामन्त्री
 जयपुर-राजस्थान

प्रतिनिधि : जिलाधिकारी, जयपुर

महामन्त्री
 जयपुर-राजस्थान

उपखण्ड ४२५/८३१
 जयपुर-राजस्थान

को सूचना एवं आदेश जारी करने हेतु।

उपखण्ड ४२५/८३१
 जयपुर-राजस्थान

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में कमेडी-मन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगाँव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में कमेडी-मन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा-मजगाँव-चौनाला मोटर मार्ग (2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु **1.050 हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम समाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated 29/12/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.050** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km)** in distt Bageshwar district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.050** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated- 29/12/2015


बिनायकरी
बागेश्वर

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No.

Dated... 29/12/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed road with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified **1.050** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km).**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.050** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Majgaun/Chaunal** Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive groups and pre-agricultural Communities. Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**


निर्वाहकारी
बगेश्वर

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 29-12-2015 at time 3:00pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Majgaun/Chaunal** area measuring **1.050** hect for the Construction of **Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.



Deputy Commissioner
Bageshwar

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated: 29.12.2015